

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2007

विषय :- अन्तर्राज्यीय संयोजन की योजना के अन्तर्गत चकराता- त्यूनी मोटर मार्ग के कि.मी. 156.00 से 171.00 एवं त्यूनी- आराकोट- शिमला मार्ग के कि.मी. 157.00 से 167.00 तक के सुधार एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2007-08)।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2286/17बजट (इन्टरस्टेट कने.)2007-08 दिनांक 12-07-2007 के संदर्भ में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एन.एच.-17014/5/2004/यू.आर./एन.एच.11 दिनांक 13 जुलाई, 2005 तथा पत्र संख्या एन.एच. 17014/4/2004-यू.आर.-एन.एच.-11 दिनांक 24.01.2007 द्वारा स्वीकृत रु० 803.39 लाख की लागत के विपरीत शासनादेश संख्या: 45/11(3)07-856(ISC)05 टी.सी.-1 दिनांक 20.03.2007 द्वारा वर्ष 2006-07 में अवमुक्त रु० 250.00 लाख, जिसमें से रुपये 180.64 लाख के उपभोग किये जाने के उपरान्त अवशेष लागत रुपये 622.74 लाख, तथा शासनादेश संख्या 264/11(3)07-856(ISC)05 टी.सी.-1 दिनांक 15.05.2007 द्वारा वर्ष 2007-08 में अवमुक्त धनराशि रुपये 45.00 लाख के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अन्तर्राज्यीय संयोजन मद में प्राविधानित धनराशि में से रु० 255.00 लाख (रु० दो करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि प्रश्नगत मार्ग के सुधार तथा सुदृढीकरण के लिए व्यय हेतु इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं, कि धनराशि का आहरण पूर्व में अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपरान्त प्रयुक्त की गयी कुल धनराशि का वर्षान्त भर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियमों का या सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार केन्द्रांश प्राप्त होने की दशा में किया जायेगा।
5. व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके विरुद्ध यह स्वीकृत किया जा रहा है।
6. कार्य की समबद्धता एवं गुणवत्ता का समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

*(हस्ताक्षर)*

7. उक्त कार्य करते समय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा। व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा, कार्य निर्धारित समय में किया जायेगा और विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि के लिये सम्बन्धित अधिशारी अभियंता उत्तरदायी होंगे, धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।
8. आगामी किश्त तभी ही स्वीकृत की जायेगी, जब उक्त धनराशि के विपरीत 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग करके पूर्व स्वीकृत व इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 04 इन्टरस्टेट कनेक्टिविटी योजना (100प्रतिशत केन्द्र पोषित)-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के अ.शा.संख्या: 284/XXVII(2)/07 दिनांक 16 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

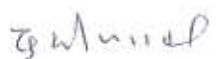
(प्रदीप सिंह रावत)  
उप सचिव।

संख्या: 472(1)/III(3)07 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड इलाहाबाद/देहरादून।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
11. लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

  
(प्रदीप सिंह रावत)  
उप सचिव।